भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1456
सोमवार, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

सरकारी/निजी क्षेत्रों में प्रदान किए गए रोजगार

1456. डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः
श्री सु॰ थिरूनवुक्करासरः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकारी/निजी क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रदान किए गए रोजगारों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा सेक्टर-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या श्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2017-18 के दौरान बेरोजगारी की दर 45 वर्षों में सबसे अधिक 6.1 प्रतिशत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) जिन क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक थी उनका क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में अधिक रोजगार सृजित करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने बेरोजगारों हेतु नए रोजगार सृजित करने का कोई लक्ष्य तय किया है और यदि हां, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) : व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की वेतन अनुसंधान इकाई (पीआरयू) की रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख मंत्रालयों/विभागों (संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर) में 2014, 2015 एवं 2016 के दौरान केन्द्र सरकार के सिविलियन नियमित कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई हैः

वर्ष (1 मार्च को)	2014	2015	2016
कर्मचारी (लाख में)	32.24	32.29	32.21

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर राज्य-वार अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) अनुबंध में दिया गया है।

(ख) एवं (ग): सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, देश में सभी आयु के व्यक्तियों हेतु सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई है:

बेरोजगारी दर (% में)			
सर्वेक्षण वर्ष	पुरूष	महिला	व्यक्ति
2017-18* (पीएलएफएस)	**6.2**	**5.7**	**6.1**
2011-12 (एनएसएस 68वां दौर)	**2.1**	**2.4**	**2.2**
2009-10 (एनएसएस 66वां दौर)	**2.0**	**2.3**	**2.0**
2004-05 (एनएसएस 61वां दौर)	**2.2**	**2.6**	**2.3**

(टिप्पणी: *तुलना हेतु, पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है)

(घ): इस अवधि के दौरान प्रमुख क्षेत्रों के अनुसार अनुमानित कार्यबल को नीचे दिया गया है:

प्रमुख क्षेत्रों के अनुसार अनुमानित कार्यबल		
क्षेत्र	**2011-12 (एनएसएस 68वां दौर)**	**2017-18* (पीएलएफएस)**
प्राथमिक	**48.9%**	**44.1%**
द्वितीयक	**24.3%**	**24.8%**
तृतीयक	**26.8%**	**31.1%**

*(टिप्पणी: *तुलना हेतु, पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है)*

(ङ) एवं (च): नियोजनीयता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार का सृजन करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने को पूर्ण करने में उनकी सहायता करेगा।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों के लिए आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

*****

अनुबंध

सरकारी/निजी क्षेत्रों में प्रदान किए गए रोजगार के संबंध में लोक सभा के दिनांक 01.07.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1456 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के आधार पर कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	ग्रामीण+शहरी		
		पुरूष	महिला	व्यक्ति
1	आंध्र प्रदेश	75.3	40.8	57.2
2	अरुणाचल प्रदेश	66.4	13.0	42.3
3	असम	74.7	11.0	43.7
4	बिहार	63.7	4.0	35.5
5	छत्तीसगढ़	76.6	47.6	62.4
6	दिल्ली	68.1	12.8	42.7
7	गोवा	64.4	22.9	42.9
8	गुजरात	74.0	19.0	47.4
9	हरियाणा	68.3	12.8	41.7
10	हिमाचल प्रदेश	71.0	47.5	58.9
11	जम्मू और कश्मीर	72.7	27.6	51.0
12	झारखंड	68.1	14.6	41.7
13	कर्नाटक	74.0	24.8	49.1
14	केरल	65.8	20.4	41.2
15	मध्य प्रदेश	75.9	31.0	54.3
16	महाराष्ट्र	71.4	29.1	50.5
17	मणिपुर	64.0	19.8	42.5
18	मेघालय	75.4	50.2	62.3
19	मिजोरम	67.1	26.0	46.4
20	नागालैंड	52.9	11.0	32.8
21	ओडिशा	72.9	18.3	44.9
22	पंजाब	69.8	13.7	42.9
23	राजस्थान	69.1	26.3	48.2
24	सिक्किम	74.0	41.6	58.7
25	तमिलनाडु	71.8	31.3	51.0
26	तेलंगाना	69.1	30.3	49.8
27	त्रिपुरा	70.5	11.1	42.0
28	उत्तराखंड	65.0	16.1	40.6
29	उत्तर प्रदेश	70.0	13.1	41.8
30	पश्चिम बंगाल	75.3	20.1	47.8
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	76.4	19.1	48.7
32	चंडीगढ़	74.0	20.0	46.9
33	दादरा और नगर हवेली	86.8	39.7	66.3
34	दमन और दीव	85.8	24.1	63.2
35	लक्षद्वीप	65.6	9.1	34.4
36	पुडुचेरी	64.4	13.4	37.8
	अखिल भारतीय	71.2	22.0	46.8

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), जुलाई, 2017 से जून, 2018, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय